

## अभावपरक दृष्टिकोण: उत्तराखंड वनाग्नि

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि आग बुझाने के लिये केंद्रीय नदिका उपयोग क्यों नहीं किया गया।

### मुख्य बंदि:

- सर्वोच्च न्यायालय ने वनाग्नि से नपिटने में उत्तराखंड सरकार द्वारा दिखाए गए 'अभावपरक' दृष्टिकोण पर उत्तराखंड के मुख्य सचवि को 17 मई को न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिये बुलाया।
- शीर्ष न्यायालय ने नरिदेश दिया कि कोई भी राज्य चुनाव ड्यूटी के लिये वन अधिकांरियों या वन वभिग के वाहनों को तैनात नहीं करेगा।
- मुख्य सचवि से वन वभिग में बड़ी रक्तिरियों, अग्नशिमन उपकरणों की कमी और नरिवाचन आयोग द्वारा दी गई वशिषिट छूट के बावजूद वन अधिकांरियों की तैनाती के बारे में भी स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।
- न्यायमूर्त बि.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ जसिमें न्यायमूर्त एस.वी.एन. भट्टी और न्यायमूर्त सिंदीप मेहता भी शामिल थे, ने कहा कि हालांकि कई कार्य योजनाएँ तैयार की जाती हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन के लिये कोई कदम नहीं उठाया जाता है।
  - वनाग्नि के कारण 1,300 हेक्टेयर भूमि प्रभावति हुई।
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सहि धामी ने परिल लाओ-पैसे पाओ मशिन की शुरुआत की थी।
  - इस अभियान के तहत, वनाग्नि को रोकने के लिये स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं द्वारा वन में पड़े परिल (चीड़ के पेड़ की पत्तियाँ) को एकत्र किया जाएगा, उनका वजन किया जाएगा तथा फरि नरिधारति परिल संग्रह केंद्र में संग्रहीत किया जाएगा।